सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स

सन्दर्भ

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 1,032 हेक्टेयर अवैध भांग की खेती को नष्ट कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस ऑपरेशन के दौरान, जब्ती करने के साथ-साथ ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने के लिए दोतरफा दृष्टिकोण अपनाया गया।
- शरीर और मन पर नशीले पदार्थों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करके सामुदायिक लामबंदी का प्रयास किया गया।
- ड्रग्स से युवाओं और बच्चों के भविष्य के लिए खतरा पैदा करने वाले खतरों के बारे में बताया गया।
- सीबीएन ने पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में अभियान चलाया है।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के बारे में

- केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भारत के राजस्व विभाग (आईआरएस) से संबद्ध है और देश के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विनियमित है।
- CBN का मुख्य कार्य अफीम उत्पादन और व्यापार को रोकना और कानूनी सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना है।
- केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव

सन्दर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की दूसरी किश्त को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करता है।
- यह आत्मानिर्भर भारत पहल को मजबूत करेगा और रोजगार पैदा करेगा।
- इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सोलर पीवी निर्माताओं का चयन किया जाएगा।
- पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत सोलर पीवी मॉड्यूल की लगभग 65 हजार मेगावाट प्रतिवर्ष निर्माण क्षमता स्थापित की जाएगी।
- इस योजना से लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश आएगा।
- इस योजना से लगभग 2 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग आठ लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा।
- नोट: पीएलआई योजना, जैसा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो न केवल विदेशी कंपनियों को देश में कार्यबल खोजने और रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि घरेलू और स्थानीय उत्पादन को भी प्रोत्साहित करती है।

भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 मसौदा

सन्दर्भ

दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

प्रमुख बिंदु

सत्यमेव जयते
Department of Telecommunications
Ministry of Communications
Government of India

- मसौदा विधेयक केवल लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचना की आवश्यकता के द्वारा विलय, डीमर्जर और अधिग्रहण, या पुनर्गठन के अन्य रूपों के ढांचे को सरल बनाने का प्रयास करता है।
- बिल केंद्र सरकार के लिए स्पेक्ट्रम असाइनमेंट करने के लिए एक स्पष्ट वैधानिक ढांचा और नियामक स्पष्टता भी निर्धारित करता है।
- बिल का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट को सबके लिए बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए और दूरसंचार सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।
- संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा विकसित करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी।

हेमकोश

संदर्भ

भारत के प्रधान मंत्री को हाल ही में नई दिल्ली में जयंत बरुआ से असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त हुई।

'हेमकोश' के बारे में

- पहला असमिया भाषा शब्दकोश, 'हेमकोश', 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में स्वर्गीय हेमचंद्र बरुआ द्वारा संकलित किया गया था।

• 'हेमकोश' डिक्शनरी के 15वें संस्करण का श्री जयंत बरुआ के नेतृत्व में अनुपालन किया गया है, और इसका निर्माण किया जा रहा है।
• 'हेमकोश' के इस संस्करण में लगभग 10,000 पृष्ठ हैं जिनमें 15 से अधिक खंड हैं।
• विशेष रूप से, हेमकोश का यह ब्रेल संस्करण ऑक्सफोर्ड के बाद ब्रेल में पहला पूर्ण भाषा शब्दकोश होगा।
• जयंत बरुआ ने दृष्टिबाधित छात्रों, विश्वविद्यालयों, राज्य और केंद्रीय पुस्तकालयों के साथ-साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को शब्दकोश प्रतियां (मुफ्त) दान करने का भी वादा किया है।
• 'हेमकोश' असमिया भाषा का पहला व्युत्पत्ति संबंधी शब्दकोश है और प्रकृति में द्विभाषी है, इस प्रकार बच्चे अंग्रेजी और असमिया दोनों भाषाओं में शब्दकोश से लाभान्वित हो सकते हैं।

भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल

सन्दर्भ

उच्च रक्तचाप के खिलाफ देश के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और मान्यता में, भारत ने अपने "इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव" के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है।

प्रमुख बिंदु

• आईएचसीआई को भारत की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के भीतर असाधारण कार्य के लिए मान्यता दी गई है।
• आईएचसीआई ने न्यूयॉर्क, यूएसए टुडे में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में '2022 यूएन इंटरएजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार पर डब्ल्यूएचओ विशेष कार्यक्रम' पुरस्कार जीता है।
• यह पुरस्कार गैर-संचारी रोगों को रोकने और नियंत्रित करने और एकीकृत जन-केंद्रित प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए भारत की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और कार्रवाई को मान्यता देता है। IHCI राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मौजूदा स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली, और उच्च रक्तचाप नियंत्रण हस्तक्षेपों का लाभ उठाने और उन्हें मजबूत करने में सक्षम रहा है।
• यह पहल 2017 में शुरू की गई थी और 23 राज्यों के 130 से अधिक जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया गया था। इस पहल के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर सहित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में उच्च रक्तचाप से पीड़ित 34 लाख से अधिक लोग इलाज करा रहे हैं।

महासागर प्रेक्षण प्रणाली रिपोर्ट कार्ड 2022

सन्दर्भ

रिपोर्ट ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम (GOOS) द्वारा जारी की गई थी।

प्रमुख बिंदु

• रिपोर्ट 2017 से सालाना प्रकाशित की जा रही है।
• रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के महासागरों में कार्बन सांद्रता का निरीक्षण करने की प्रणाली अपर्याप्त है, क्योंकि मानव गतिविधियों के कारण प्रतिवर्ष वायुमंडल में उत्सर्जित 40 गीगाटन कार्बन का 26% महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है।
• GOOS महासागर के निरंतर अवलोकन के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। यह एक अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) के नेतृत्व वाला कार्यक्रम है। आईओसी यूनेस्को का हिस्सा है।
• IOC अंतर्राष्ट्रीय एग्रो कार्यक्रम का समर्थन करता है जो लगभग 3,800 तैरते रोबोटिक उपकरणों की एक वैश्विक सारणी रखता है जो दुनिया के महासागर के ऊपरी 2,000 मीटर के दबाव, तापमान और लवणता को मापते हैं।
• एक अन्य नेटवर्क, जिसे ग्लोबल ट्रॉपिकल मूर्ड बॉय एरे (जीटीएमबीए) कहा जाता है, जो सभी महासागरीय घाटियों में फैले मूरिंग्स का एक विशाल नेटवर्क है, एनओएए, यूएसए द्वारा समर्थित है।

सीमा शुल्क एक योजना

सन्दर्भ

सरकार सभी बंदरगाहों पर सभी मंजूरियों को तेजी से ट्रैक करने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु

• विचार यह सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करना है कि आयात और निर्यात के लिए माल बंदरगाह और हवाई अड्डों पर उनके आगमन के एक घंटे के भीतर साफ हो जाए।
• वर्तमान में, माल एयर कार्गो के लिए 24-48 घंटे और समुद्री कार्गो निकासी के लिए 72 घंटे तक का समय लेता है।
• इससे भारत को 2047 तक वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2021 के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित, भारत का 2020 में वैश्विक निर्यात 1.6% और वैश्विक आयात में 2.1% का योगदान रहा।

तेजी से निकासी के लिए किए गए अन्य उपाय

• स्विफ्ट (व्यापार की सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस) की शुरुआत।

• डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधाएं - सिस्टम आयातकों के एक चुनिंदा समूह को आगमन के 48 घंटों के भीतर बंदरगाह से सीधे कार्गो को साफ करने की अनुमति देता है।

भारत@2047

• वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार किया गया कस्टम वन प्लान India@2047 ब्लूप्रिंट का हिस्सा है।
• भारत@2047 देश को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने और 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने का एक दृष्टिकोण है।

अन्य योजनाएं हैं:

आत्म निर्भर भारत पहल के विस्तार के रूप में भारत के बाहर आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना।
100 भारतीय ब्रांडों को वैश्विक चैंपियन के रूप में प्रोजेक्ट करना ।
मुक्त व्यापार समझौता भागीदार देशों की सहायता से विश्व व्यापार संगठन में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करना।

सामरिक गैस भण्डार

सन्दर्भ

भारत अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) की तर्ज पर एक सामरिक गैस भण्डार स्थापित करने की योजना में तेजी ला रहा है।

पृष्ठभूमि

• भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है।
• वित्त वर्ष 2012 में प्राकृतिक गैस के आयात और स्थानीय उत्पादन के परिणामस्वरूप देश में 64.8 अरब घन मीटर की आपूर्ति हुई।
• भारत ने वित्तीय वर्ष 2022 में 34.02 अरब मानक घन मीटर का उत्पादन किया।
• गेल के हाल के विकास ने रूस के गज़प्रोम से अपने अनुबंधित उत्पाद को सुरक्षित करने में विफल रहने और हाजिर बाजारों में अत्यधिक कीमतों पर खरीदने के लिए सामरिक भंडारण की योजनाओं को तेज कर दिया है।
• मौजूदा कीमत (जिस पर गेल को मजबूरन खरीदना पड़ता है) पहले अनुबंधित (गजप्रोम के साथ) की तुलना में काफी अधिक है, जो $15-17 प्रति एमएमबीटीयू के बीच है।

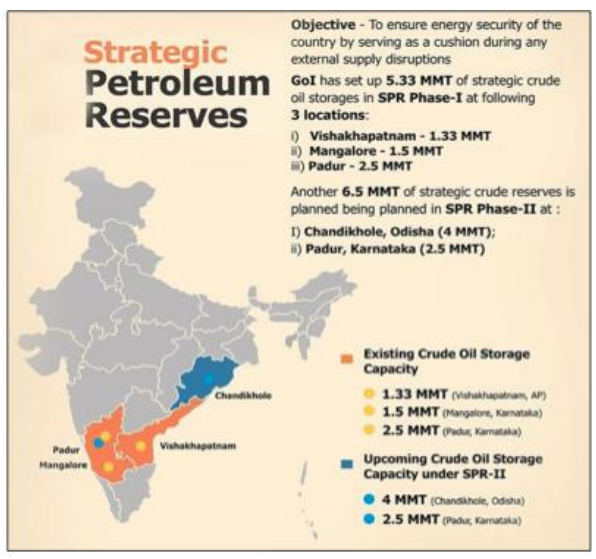

योजना के बारे में

• मौजूदा तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) सुरंगों और खाली तेल के कुओं का उपयोग गैस भंडार के लिए किया जा सकता है, साथ ही बड़े नमक गुफाओं जैसे नए भूमिगत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
• भंडारण सुविधाओं को पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे के करीब चुना जा सकता है ताकि जरूरत के समय ईंधन को आसानी से ले जाया जा सके।
• भारत भी अपने राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 20,000 किमी से बढ़ाकर 35,000 किमी कर रहा है।
• देश की गैस मांग उर्वरक उद्योग, बिजली, शहर गैस वितरण और इस्पात क्षेत्रों द्वारा संचालित होने की उम्मीद है।
• भारत में विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में 5.33 मिलियन टन भूमिगत सामरिक तेल भंडार सुविधाएं हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

मिजोरम और असम सीमा विवाद

सन्दर्भ

असम के मुख्यमंत्री और मिजोरम के उनके समकक्ष ने हाल ही में नई दिल्ली में दोनों राज्यों के बीच सीमा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की और लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए एक क्षेत्रीय समिति बनाने पर सहमति व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु

• मिजोरम असम के साथ 164.6 किमी लंबी अंतर-राज्यीय सीमा साझा करता है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, जो अब तक अनसुलझा है।
• मिजोरम 1972 तक असम का हिस्सा था जब इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था।

• सीमा विवाद मुख्य रूप से दो औपनिवेशिक अधिसूचनाओं- 1875 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) के तहत अधिसूचित इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट और 1933 में सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में दर्शाई गई सीमा से निकला था।
• मिजोरम ने जहां इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट के 509 वर्ग मील के हिस्से को अपनी वास्तविक सीमा के रूप में दावा किया, वहीं असम ने कहा कि 1933 की सीमा इसकी संवैधानिक सीमा थी। सीमा पर खासकर 1994 के बाद कई झड़पें हुई हैं, और अब यह 2018 के बाद से लगातार हो रही है।

ऑपरेशन ऑक्टोपस

सन्दर्भ
सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि बिहार और झारखंड अब माओवादियों से मुक्त हो गया है.

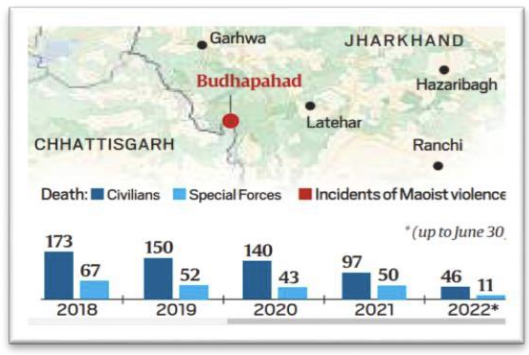

प्रमुख बिंदु
• सुरक्षा बल पहली बार बुद्ध पहाड़ पहुंचे। उन्होंने पिछले तीन दशकों से इस पर हावी रहे माओवादियों से इसका सफाया कर दिया।

• बुद्ध पहाड़ झारखंड में लातेहार और गढ़वा जिलों और पड़ोसी छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के त्रि-जंक्शन में एक जंगली क्षेत्र है।
• सीआरपीएफ अप्रैल 2022 से झारखंड में 'ऑपरेशन ऑक्टोपस' चला रहा है।
• उससे पहले के अन्य ऑपरेशन - 'ऑपरेशन डबल बुल' और 'ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म', आदिवासी इलाकों में अभी भी चल रहे हैं।

इनविजिबल रिपोर्ट

सन्दर्भ
WHO ने एक नई रिपोर्ट जारी की है: 'इनविजिबल रिपोर्ट - द टू स्केल ऑफ़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज '।

प्रमुख बिंदु
• हृदय रोगों (सीवीडी) के कारण सबसे अधिक एनसीडी से होने वाली मौतों के बाद पुरानी सांस की बीमारियों का स्थान है। सीवीडी से होने वाली 86 फीसदी मौतों को रोकथाम
और उपचार के जरिए रोका या नियंत्रित किया जा सकता था।
• वैश्विक स्तर पर मधुमेह के 95 प्रतिशत से अधिक मामले टाइप 2 मधुमेह के हैं।
• उच्च रक्तचाप वाले 2/3 लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
• 2022 में, केवल कुछ ही देश 2030 तक एनसीडी से होने वाली असामयिक मौतों को कम करने के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की राह पर थे।

अवरुद्ध राशि (एएसबीए) द्वारा समर्थित आवेदन

सन्दर्भ
सेबी सेकेंडरी मार्केट के लिए ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) जैसी संरचना द्वारा समर्थित एक एप्लिकेशन के साथ आने की सोच रहा है।

प्रमुख बिंदु
• एएसबीए एक आवेदन है जिसमें प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की सदस्यता लेने के लिए बैंक खाते में आवेदन राशि को अवरुद्ध करने के लिए एक प्राधिकरण है।
• यदि कोई निवेशक एएसबीए के माध्यम से आवेदन कर रहा है, तो उनके आवेदन का पैसा बैंक खाते से तभी डेबिट किया जाएगा जब आवंटन के आधार को अंतिम रूप देने के बाद आवंटन के लिए आवेदन का चयन किया जाता है।

बेराकटार TB2

सन्दर्भ
तुर्की की रक्षा फर्म बायकर ने संयुक्त अरब अमीरात को 20 सशस्त्र ड्रोन वितरित किए।

प्रमुख बिंदु
यह एक मध्यम ऊंचाई, लम्बे समय तक चलने वाला (MALE) मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (यूसीएवी) है जो दूर से नियंत्रित या स्वायत्त उड़ान संचालन में सक्षम है। इनकी उड़ान रेंज 300 किमी तक और ऊंचाई 5.5 किमी तक होती है।
इसका उपयोग टोही, निगरानी और जमीनी हमले के लिए किया जा सकता है। वे लेजर निर्देशित कवच भेदी बमों से भरे हुए हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com